श्री मंगुभाई पटेल

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

का

अभिभाषण

मध्यप्रदेश विधानसभा अधिवेशन

5 फाल्गुन, 1943 शक भोपाल, सोमवार 7 मार्च, 2022

माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण,

1. सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत।
2. पन्द्रहवीं विधानसभा के चौथे बजट सत्र में सदन को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत सुखद अनुभूति हो रही है। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, मैं स्वाधीनता संघर्ष के सभी ज्ञात-अज्ञात नायकों के अमर बलिदानों का पुण्य-स्मरण कर उन्हें शत-शत नमन करता हूँ। आजादी के अमृत-काल में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विश्व-पटल पर इक्कीसवीं सदी के आत्म-निर्भर भारत का उदय हो रहा है। "सबका- साथ – सबका विकास – सबका प्रयास-सबका विश्वास" ही भारत- मंत्र बन गया है। मेरी सरकार, राज्य के साढ़े आठ करोड़ नागरिकों के सहयोग से समृद्ध, विकसित और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए कृत-संकल्पित होकर कार्य कर रही है।
3. कोविड–19 इस सदी की सबसे घातक महामारी के रूप में सामने आई है और इसने सम्पूर्ण विश्व की अर्थ- व्यवस्था, राज–व्यवस्था, कार्य करने के तरीकों और जीवन–शैली को प्रभावित किया है। ये इस देश की मिट्टी और 130 करोड़ जनता की ताकत ही है कि जब-जब भी हम पर किसी प्रकार का संकट

आया है, तब-तब भारत उस संकट के सामने मज़बूर नहीं, बल्कि और मज़बूत होकर उभरा है।

4. माननीय प्रधानमंत्री जी के सतत और सक्रिय मार्गदर्शन में देश ने कोरोना की तीन लहरों का न केवल डटकर मुकाबला किया, बल्कि इस आपदा को राष्ट्र के नवनिर्माण के अवसर में बदल दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने "सबको वैक्सीन–मुफ्त वैक्सीन" लगवाने का जो दूरदर्शी और जन-हितैषी निर्णय लिया, वही आज सुरक्षा–कवच बनकर करोड़ों भारतीयों के प्राणों की रक्षा कर रहा है। देश भर में अभियान के रूप में कोविड टीकाकरण होने से कोरोना की तीसरी लहर, कहर नहीं बन पायी। ये इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि जब देश का नेतृत्व करने वाले हौसले के साथ फैसले लेते हैं, तो जन-जन की जिंदगी बदल जाती है।

5. मध्यप्रदेश में मेरी सरकार ने जहाँ एक ओर कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के सभी संभव उपाय किये, वहीं दूसरी ओर अर्थ-व्यवस्था को भी पटरी से नहीं उतरने दिया। सरकार ने जितनी चिंता कोविड-रोकथाम, कोविड–अनुकूल व्यवहार और अस्पताल-प्रबंधन के लिए की, उतनी ही चिंता गरीब की रोजी-रोटी, बच्चों की शिक्षा, युवाओं के रोज़गार, विकास के काम और जन–कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने की भी की। यही कारण है कि विगत लगभग दो वर्ष में कोविड की

कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी मध्यप्रदेश तेजी से आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है।

6. लोकतंत्र की सार्थकता "जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन" में निहित है और मेरी सरकार ने इसे सही मायने में चरितार्थ करके दिखाया है। नीति निर्माण से लेकर निर्णय लेने तक और निर्णयों के क्रियान्वयन से लेकर सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग तक–हर क्षेत्र में जनता की भागीदारी और जनता के सहयोग ने सफलता का एक नया इतिहास रच दिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स के माध्यम से कोरोना–प्रबंधन, मैं कोरोना वालेंटियर अभियान, युवा शक्ति–कोरोना मुक्ति अभियान, योग से निरोग कार्यक्रम, ऊर्जा साक्षरता अभियान, अंकुर कार्यक्रम, एडॉप्ट एन आँगनवाड़ी अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप निर्माण, बजट निर्माण और आनंदकों के सहयोग से आनंद गतिविधियों का आयोजन आदि अनेक कार्यों में मध्यप्रदेश में जनता की सक्रिय भागीदारी ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। मेरी सरकार ने लोक और तंत्र की सहभागिता से सरकार के संचालन का एक अभिनव मॉडल पूरे देश के समक्ष प्रस्तुत किया है।

7. मेरी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2024-25 तक देश की अर्थ-व्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर पहुँचाने के लक्ष्य की पूर्ति में अपना अधिकतम योगदान देने के लिए कृत-संकल्पित है। इस वर्ष प्रदेश का राज्य सकल घरेलू उत्पाद 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक होना संभावित है, जो प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय है।

8. मेरी सरकार ने अर्थ-व्यवस्था को गति देने के लिए अधोसंरचनात्मक पूँजीगत कार्यों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया है। इस वित्त वर्ष की प्रथम छः माही में प्रदेश का पूँजीगत व्यय पिछले दो वर्ष की तुलना में क्रमशः 40 एवं 96 प्रतिशत अधिक रहा है। मेरी सरकार के प्रयासों से प्रदेश में जीएसटी पंजीयत करदाताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जीएसटी करदाताओं से विवरणी प्रस्तुत कराने में प्रदेश, देश के प्रथम पाँच राज्यों में है।

9. भौतिक अधोसंरचना का सतत विकास राज्य की प्रगति का प्रतिबिम्ब है। मेरी सरकार आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के प्रमुख स्तम्भ के रूप में अधोसंरचना-विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। ग्वालियर – चम्बल क्षेत्र के लिए वरदान 309 किलोमीटर लम्बाई के अटल प्रगति-पथ और प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ने वाले 906 किलोमीटर लम्बाई के

नर्मदा प्रगति-पथ का निर्माण प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

10. मेरी सरकार का विगत लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल सड़क अधोसंरचना के विकास की दृष्टि से स्वर्णिम रहा है। इस अवधि में भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में 3 हजार 251 किलोमीटर लंबाई के 26 हजार 222 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले 90 मार्ग स्वीकृत हुए हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 379 किलोमीटर लंबाई की 5 हजार 301 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 6 नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियाजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। मेरी सरकार सड़क मार्गों के निर्माण के साथ–साथ उनके संधारण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। सड़क–सुरक्षा हेतु सड़कों के ब्लैक स्पॉट्स का ट्रीटमेंट प्राथमिकता पर किया जा रहा है। प्रदेश के प्रमुख 200 मार्गों का आधुनिक यातायात सर्वेक्षण और सभी टोल प्लाजा को कम्प्यूटरीकृत एवं स्वचालित करने की कार्यवाही की जा रही है।

11. मेरी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता में मध्यप्रदेश, देश में

प्रथम स्थान पर तथा सड़कों की लंबाई में देश के प्रथम 7 राज्यों में सम्मिलित है।

12. मेरी सरकार विद्युत क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य की विद्युत मांग की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अति उच्च दाब उप केन्द्रों एवं उससे संबंधित लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह में 4 हजार 666 करोड़ रुपये की लागत से 660 मेगावॉट क्षमता की नई इकाई की स्थापना प्रस्तावित है। भारत सरकार की रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में प्रदेश में वर्ष 2025-26 तक 15 हजार 434 करोड़ रुपये के कार्य किए जाने का लक्ष्य है। फ्लेट दरों पर विद्युत प्रदाय से साढ़े 22 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। एक हेक्टेयर तक की भूमि एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति के 8 लाख कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

13. मेरी सरकार गैर पारम्परिक ऊर्जा एवं नवकरणीय ऊर्जा के सुनियोजित विकास के लिए संकल्पित है। प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता 5 हजार 100 मेगावॉट हो गई है। इस वर्ष 1 हजार 500 मेगावॉट की आगर-शाजापुर-नीमच सोलर पार्क परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। सागर में 1 हजार 500 मेगावॉट क्षमता के सोलर पार्क के लिए भूमि

चिन्हित कर ली गई है। ओंकारेश्वर में 3 हजार करोड़ की लागत की विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावॉट क्षमता की सोलर फ्लोटिंग परियोजना के लिए 2 हजार हेक्टेयर जल-क्षेत्र चिन्हांकित कर लिया गया है। रुपए 4 हजार करोड़ की लागत की 750 मेगावॉट क्षमता की पवन सोलर हाइब्रिड परियोजना की कार्यवाही प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में जुलाई, 2023 तक 45 हजार नग सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य है। ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ कर विद्यार्थियों और सभी नागरिकों को ऊर्जा उत्पादन, नवकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा बचत की जानकारी दी जा रही है।

14. हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुँचे, यह मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अप्रैल, 2020 की स्थिति में प्रदेश में 17 लाख 72 हजार यानी 14.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध था, लेकिन वर्तमान में 47 लाख 15 हजार यानी 38.55 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का शुद्ध जल उपलब्ध होने लगा है। अब तक प्रदेश के 4 हजार 85 ग्रामों के शत- प्रतिशत घरों में नल से जल पहुँचाया जा चुका है। वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन में राशि उपयोग में मध्यप्रदेश,देश में दूसरे स्थान पर है तथा हर घर जल उपलब्ध करवाने में मध्यप्रदेश, देश के 7 बड़े राज्यों में तीसरे स्थान पर है।

15. मेरी सरकार के सतत् प्रयासों से जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से प्रदेश की सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर से भी अधिक हो गयी है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में 14 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा वाली 45 हजार करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा 44 हजार 605 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। परियोजना से प्रदेश में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर में सिंचाई और 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त 103 मेगावॉट जल विद्युत एवं 27 मेगावॉट सौर ऊर्जा भी उपलब्ध होगी।

16. मध्यप्रदेश, देश के हृदय में बसता है और खेती–किसानी मध्यप्रदेश के हृदय में बसती है। प्रदेश के किसानों के पसीने की एक भी बूंद व्यर्थ न जाए तथा फसल उत्पादन और आमदनी दोनों तेजी से बढ़ें, यही सरकार का लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्रीजी ने जीरो बजट की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने का आव्हान किया है। प्रदेश में इस वर्ष 99 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य है। जैविक खेती में मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2019-20 में प्रदेश का कुल कृषि निर्यात 1.25 लाख मीट्रिक टन था, जो अब 46 प्रतिशत बढ़कर 1.83 लाख मीट्रिक टन हो गया है।